[2017] 3 एस. सी. आर. 458

पवन कुमार

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 775/2017)

अप्रैल 28, 2017

[दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर और मोहन एम. शांतनगौदर, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: आई. पी. सी. की धारा 363, 366 और 376 के तहत एक मामले में बरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आरोपी सूचना देने वाले की बेटी को धमकी देता था कि वह उसका अपहरण कर लेगा और लगातार उसे चिढ़ाता रहता था- लड़की ने खुद को आग लगा कर आत्महत्या कर ली-हेड कांस्टेबल द्वारा पीड़ितके मृत्युकालिक कथन को दर्ज करना और उसके बाद पीड़ितने दम तोड़ दिया- निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया, हालांकि, उच्च न्यायालय ने आरोपी को धारा 376 के तहत दोषी ठहराया और तदनुसार सजा सुनाई- माना गयाः फिटनेस का प्रमाण पत्र कानून की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार, इसके अभाव में, मृत्युकालिक कथन की अवहेलना करने का कोई कारण नहीं था- हेड कांस्टेबल ने मृत व्यक्ति द्वारा सुनाए गए मृत्युकालिक कथन को दर्ज किया और मृतक ने लिखा कि केवल आरोपी ही उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार था- वही डॉक्टर की उपस्थिति में दर्ज किया गया था जिसने उसके हस्ताक्षर किये थे-निचली अदालत को जलने की चोटों से दूर कर दिया गया था, जबकि एक पूर्ण नियम नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसे 80 प्रतिशत जलने की

चोटें आई हैं वह मृत्युकालिक कथन नहीं कर सकता है-इसके अलावा, मृत्युकालिक कथन की पुष्टि अन्य गवाहों द्वारा की गई थी-माता-पिता की गवाही पूरी तरह से निर्दोष थी और विश्वास के योग्य थी-आरोपी ने अपने सक्रिय कृत्यों से ऐसी स्थिति पैदा की थी जिसने लड़की को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया- कोई भी सामग्री नहीं मिली कि पीड़ितअतिसंवेदनशील थी-आरोपी ने आत्मसम्मान और आत्मसम्मान को धूमिल करने में सक्रिय भूमिका निभाई। अभियुक्त ने पीड़ित के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को धूमिल करने में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसने उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया-इस प्रकार, उच्च न्यायालय दोषमुक्ति को पलटने और तदनुसार सज़ा सुनाने हेतु सही था- साक्ष्य- मृत्युकालिक कथन।

धारा 306-आत्महत्या के लिए उकसाना- जब ध्यान खिंचा गया है-समझाया गया।

साक्ष्य- मृत्युकालिक कथन-डॉक्टर द्वारा घोषित योग्यता का प्रमाण पत्र-रखने की आवश्यकताः- डॉक्टर द्वारा योग्यता का प्रमाण पत्र कानून की आवश्यकता नहीं है। ईव टीज़िंग-अदालत द्वारा महिलाओं की ईव टीज़िंग की प्रथा की निंदा की गई-ईव टीज़िंग महिलाओं के लिए उत्पीड़न का कारण बनती है-यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 के तहत महिलाओं के अधिकार को प्रभावित करती है- अनुच्छेद 14,15 और 21 शब्द और वाक्यांशः शब्द 'उकसाना'- इसका अर्थ, उप-धारा 376, 107 दंड संहिता, 1860 के संदर्भ में। शब्द 'उकसाना' और 'आगे बढ़ने का आग्रह करना'- अर्थ। अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहाः 1.1 मूल रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच पर -मृत्युकालिक कथन- एक्स. पीडब्लू-10/ए, यह पाया गया कि हेड कांस्टेबल ने वही लिखा था जो मृतक ने कहा था और उसके बाद मृतक ने लिखा था कि उसकी मौत के लिए अकेले आरोपी जिम्मेदार था। हेड कांस्टेबल द्वारा दर्ज किया गया

मृत्युकालिक कथन, आरोपी द्वारा पीड़ित को लगातार चिढ़ाने के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है। यही बात डॉक्टर, पीडब्लू-10 की उपस्थिति में दर्ज की गई है, जिन्होंने उनके हस्ताक्षर किए थे। पीडब्लू-10 अपनी गवाही में दृढ़ रहा है कि पीड़ित बोलने के लिए उपयुक्त स्थिति में था। लगातार जिरह के बावजूद उनसे पूछताछ की गई लेकिन वो अपने कथन से डिगे नहीं। निचली अदालत ने इस आधार पर पीडब्लू-10 की गवाही की अवहेलना की कि फिटनेस का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। मृत्युकालिक घोषणा की अवहेलना करने का कोई कारण नहीं है। फिटनेस का प्रमाण पत्र कानून की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण कोर्ट जलने की चोटों से प्रभावित हुआ था। एक पूर्ण नियम नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसे 80 प्रतिशत जलने की चोटें आई हैं, वह मृत्युकालिक घोषणा नहीं कर सकता है। उसकी मृत्युकालिक घोषणा को अन्य गवाहों से समर्थन मिला। पुष्टि करने वाले साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर सही ढंग से भरोसा किया और निचली अदालत के निष्कर्ष को उलट दिया। [पैरा 24,27,281 (474-ई-एफ;477-ए-बी,एच;478-ए] गुलजारी लाल बनाम हरियाणा राज्य (2016) 4 एस. सी. सी. 583; लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 6 एस. सी. सी. 710; अतबीर बनाम एन. सी. टी. दिल्ली सरकार (2010) 9 एस. सी. आर. 993: (2010) 9 एस. सी. सी. 1-पर भरोसा किया गया।

1.2 जहाँ तक पीडब्लू-1 और पीडब्लू-9 के साक्ष्य की विश्वसनीयता का सवाल है, पीड़ित के माता-पिता का कहना है कि उनके बयान को विश्वसनीय नहीं मानने के कारण इस तथ्य पर आधारित हैं कि उन्होंने ग्राम पंचायत को लिखित रूप में घटना की सूचना नहीं दी थी। साक्ष्य को पूरी तरह से देखने पर, यह पाया जाता है कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा किए गए विश्लेषण को उचित रूप से हटा दिया। विभिन्न परिस्थितियों के संबंध में साक्ष्य की गुण दोष विवेचना की जानी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरोपी को पहले के अपराध में बरी कर दिया गया था

और वह पीड़ित के लिए लगातार उपद्रव बन गया था। ऐसे में गरीब माता-पिता के पास ग्राम पंचायत में शिकायत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह मानना कि उनका साक्ष्य निंदनीय है क्योंकि शिकायत लिखित रूप में नहीं दी गई थी, विकृत दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। साक्ष्य को पूरी तरह से देखने पर, यह पाया जाता है कि माता-पिता की गवाही पूरी तरह से निर्विवाद है और विश्वास के योग्य है। [पैरा 29] [478-बी. डी.]

1.3 आई. पी. सी. की धारा 307 में 'उकसाना' शब्द की व्याख्या नहीं की गई है। इस संदर्भ में, धारा 107 के तहत प्रदान की गई उकसाने की परिभाषा प्रासंगिक है। धारा 376 उन लोगों को दंडित करने का प्रयास करती है जो दूसरों को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं। व्यक्ति ने दूसरे को आत्महत्या के लिए उकसाया है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से एकत्र किया जाना चाहिए और आरोपी के निरंतर आचरण से पता लगाया जाना चाहिए, जिसमें उसका मानसिक तत्व शामिल है। ऐसी आवश्यकता को आई. पी. सी. की धारा 107 को पढ़ने से समझा जा सकता है। "प्रोत्साहन", इस प्रकार, कार्य करने के लिए सक्रिय सुझाव या समर्थन की निश्चित मात्रा का अर्थ है। "उकसाना" शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए उकसाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, उकसाना, उकसाना या प्रोत्साहित करना। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को तब उकसाने के लिए कहा जाता है जब वह उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी माध्यम या भाषा से सक्रिय रूप से किसी कार्य के लिए सुझाव देता है या उत्तेजित करता है, चाहे वह स्पष्ट अनुरोध का रूप ले या संकेत, आक्षेप या प्रोत्साहन का रूप ले। प्रेरणा (व्यक्त) शब्दों में हो सकती है या (निहित) आचरण द्वारा हो सकती है। "आगे बढ़ने का आग्रह" शब्द का अर्थ है किसी को कुछ करने के लिए मनाने के लिए सलाह देना या कड़ी मेहनत करना, किसी व्यक्ति को विशेष दिशा में अधिक तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, विशेष रूप से ऐसे

व्यक्ति को धक्का देकर या मजबूर करके। इसलिए, दूसरे को उकसाने वाले व्यक्ति को दूसरे के साथ किसी कार्य को करने के लिए उकसाने, उकसाने या प्रोत्साहित करने के इरादे से दूसरे को "उकसाना" या "आगे बढ़ाना" पड़ता है। उकसाने को साबित करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि आरोपी मृतक को शब्दों, ताने से तब तक उकसाता या परेशान करता रहा जब तक कि मृतक प्रतिक्रिया नहीं देता। एक अनौपचारिक टिप्पणी या नियमित या सामान्य बातचीत में कही गई किसी बात को "उकसाने" के रूप में नहीं माना जाना चाहिए या गलत नहीं समझा जाना चाहिए। [पैरा 32,35) (478-जी-एच; 480-डी-ई, एफ-जी; 479-एफ]

चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) [2009) 13 एस. सी. आर. 230: (2009) 16 धारा 605; रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [2001] 4 पूरक एस. सी. आर. 247: (2001) 9 एस. सी. सी. 618; रणधीर सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य [2004) 5 पूरक एस. सी. आर. 351: (2004) 13 एस. सी. सी. 129; प्रवीण प्रधान बनाम उत्तरांचल राज्य और दूसरा [2012] 8 एस. सी. आर. 1129: (2012) 9 एस. सी. सी. 734; अमलेंदु पाल उर्फ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [2009) 15 एस. सी. आर. 836: (2010) 1 एस. सी. सी. 707; किशोरी लाल बनाम एम. पी. राज्य। [2007] 7 एस. सी. आर. 1051: (2007) 10 एस. सी. सी. 797; किशनगिरी मंगलगिरी गोस्वामी बनाम गुजरात राज्य [200911 एस. सी. आर. 672: (2009) 4 एस. सी. सी. 52; नेताजी दत्ता बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य (2005) 2 एस. सी. सी. 659-संदर्भित।

1.4 अभियुक्त की ओर से घटना के समय के निकट किसी भी सकारात्मक कार्रवाई के बिना उत्पीड़न का आरोप, जिसके कारण एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, आई. पी. सी. की धारा 306 के संदर्भ में दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है। एक अनौपचारिक

टिप्पणी जो सामान्य मामलों में उत्पीड़न का कारण बन सकती है, उकसावे के दायरे में नहीं आएगी। केवल फटकार या गुस्से में एक शब्द उकसाने का दर्जा नहीं अर्जित करेगा। सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जो पीड़ित के लिए जीवन को समाप्त करने की स्थिति पैदा करे। [पैरा 411 [484-सी. डी.] 1.5 तात्कालिक मामले में, अभियुक्त ने अपने कृत्यों और अपने निरंतर आचरण से ऐसी स्थिति पैदा की थी जिसके परिणामस्वरूप मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। अभियुक्त के सक्रिय कृत्यों ने मृतक को अपने जीवन का अंत करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं पाई गई है जो अदालत को यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर करती है कि आत्महत्या करने वाली पीड़ित सामान्य कलह, कलह और घरेलू जीवन में अंतर के प्रति अतिसंवेदनशील थी जो उस समाज के लिए काफी सामान्य थी जिससे पीड़ित संबंधित थी। दूसरी ओर, आरोपी ने पीड़ित के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को धूमिल करने में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे पीड़ित लड़की ने आत्महत्या कर ली। वास्तव में उसके साथ हुई क्रूरता ने उसे अपनी जीवन की लौ को बुझाने के लिए प्रेरित किया। [पैरा 42] [484-ई-एफ] 1.6 उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को केवल मृत्युकालिक घोषणा के आधार पर उलट नहीं दिया। इसने माता-पिता और अन्य गवाहों के साक्ष्य पर भी भरोसा किया। इसने ग्राम पंचायत के प्रधान के संस्करण को भी विश्वसनीय माना। इन सभी गवाहों ने गवाही दी कि आरोपी बरी होने के बाद लड़की को धमकी देने और चिढ़ाने में लगा हुआ था। उसने उसे शांति से रहने नहीं दिया। [पैरा 43] एफ 484-जी] 1.7 उसका उत्पीड़न असहनीय और असह्य हो गया था। पिता ने गवाही दी थी कि लड़की ने बताया था उन्होंने कई बार इसकी शिकायत प्रधान से की थी। ये सभी अभियुक्त द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका के बराबर हैं। यह ऐसी स्थिति नहीं है जहां कोई व्यक्ति एक ही कार्य पर अपमानित महसूस करता है। यह पूरी तरह से एक अलग स्थिति है। गाँव

में रहने वाली युवा लड़की को लगातार धमकाया और छेड़ा जाता था। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। इस बात के प्रमाण हैं कि माता-पिता समाज के गरीब वर्ग से हैं। जैसा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है, जब उनकी बेटी के मामले को दूसरे अस्पताल में भेजा गया तो पिता उसका इलाज नहीं कर सकते थे। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त का आचरण पूरी तरह से सक्रिय था। [पैरा 44] [484-एच; 485-ए-सी]

1.8 तात्कालिक मामला मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न के मामले को प्रमुखता से पेश करता है। इस न्यायालय को यह कहते हुए दुख हो रहा है कि एक सभ्य समाज में छेड़छाड़ से शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जो केवल यह दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति आवश्यक सम्मान की भावना सामाजिक रूप से विकसित नहीं की गई है। एक पुरुष की तरह एक महिला की भी अपनी जगह होती है। उन्हें अनुच्छेद 14 (संविधान) के तहत उतनी ही समानता प्राप्त है जितनी एक पुरुष को है। अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी के अनुसार गरिमा के साथ जीने के अधिकार का छेड़छाड़ के अप्रिय कृत्य में लिप्त होकर उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यह लैंगिक संवेदनशीलता और न्याय की मौलिक अवधारणा और अनुच्छेद 14 के तहत एक महिला के अधिकारों को प्रभावित करता है। इसके अलावा यह एक महिला के अधिकार में एक लाइलाज सेंध लगाता है जो अनुच्छेद 15 के तहत उसके पास है। यह सोचने के लिए मजबूर किया जाता है कि इस देश में महिलाओं को शांति से रहने और गरिमा और स्वतंत्रता के साथ सशक्त जीवन जीने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है। यह ध्यान में रखना होगा कि उसे जीवन का अधिकार है और वह अपनी पसंद के अनुसार प्रेम करने का हकदार है। उसे अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है। उसके पास एक व्यक्तिगत विकल्प है

जिसे कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। सामाजिक रूप से इसका सम्मान किया जाना चाहिए। [पैरा 45) (485-ई-एच; 486-ए]

1.9 सभ्य समाज में पुरुष वर्चस्ववाद के लिए कोई जगह नहीं है। भारत का संविधान महिलाओं को सकारात्मक अधिकार प्रदान करता है और उक्त अधिकार संविधान के अनुच्छेद 15 से बोधगम्य हैं। जब संविधान के तहत अधिकार प्रदान किया जाता है, तो यह समझना होगा कि कोई उपेक्षा नहीं है। एक आदमी को अपने अहंकार या उस मामले के लिए, मर्दानगी को एक आधार पर नहीं रखना चाहिए और सभ्यता की अवधारणा को नहीं छोड़ना चाहिए। अहंकार को कानून के आगे झुकना चाहिए। इस संदर्भ में समानता को संवैधानिक सिद्धांत का सारांश माना जाना चाहिए। तात्कालिक मामला आरोपी की निंदनीय भ्रष्टता को दर्शाता है जिसके कारण एक युवा लड़की के लिए दिल दहला देने वाली स्थिति पैदा हो गई जिसे अपने जीवन को समाप्त करने के लिए मजबूर किया गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को उलट दिया और सजा सुनाई। इसने उपयुक्त रूप से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया और उसी के साथ सहमति है। [पैरा 46) (486-बी-सी] पुलिस उप महानिरीक्षक और एक अन्य बनाम एस. समुथिरम [2012) 11 एस. सी. आर. 174: (2013) 1 एस. सी. सी. 598; जदुनाथ सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1971) 3 एस. सी. सी. 577; शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [1974] 1 एस. सी. आर. 489: (1973) 2 एस. सी. सी. 793; कर्नाटक राज्य बनाम के. गोपालकृष्णन (2005) 9 एस. सी. सी. 291; एल. आर. द्वारा गिरिजा प्रसाद (मृत) बनाम एमपी राज्य। [2007) 9 एस. सी. आर. 483: (2007) 7 एस. सी. सी. 625; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजय कुमार [20081 2 एस. सी. आर. 552: (2008) 3 एस. सी. सी. 351; राजस्थान राज्य बनाम सोहन लाल [2004] 1 पूरक एस. सी. आर. 480: (2004) 5 एस. सी. सी. 573; चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य [2007] 2 एस. सी. आर. 630:

(2007) 4 एस. सी. सी. 415; विजय पाल बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) [2015] 3 एस. सी. आर. 394: (2015) 4 एस. सी. सी. 749-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1974] 1 एस. सी. आर. 489 पैरा 9

(2005) 9 धारा 291 पैरा 11

(2007)9 एस. सी. आर. 483 को संदर्भित पैरा 12

(2008) 2 एस. सी. आर. 552 को संदर्भित पैरा 13

(2004) पूरक एस. सी. आर. 480 पैरा 13

(2007) 2 एस. सी. आर. 630 पैरा 14

(2016) 4 एस ई सी 583 पैरा 21

(2002) 6 एस ई सी 110 पर निर्भर करता है पैरा 24

(2010) 9 एस. सी. आर. 993 पैरा 25

(2015) 3 एस. सी. आर. 394 पैरा 27

(2009) 13 एस. सी. आर. 230 पैरा 33

(2001) 4 पूरक एस. सी. आर. 247 पैरा 33 को संदर्भित करता है।

(2004) 5 पूरक एस. सी. आर. 351 पैरा 36 को संदर्भित करता है।

(2012) 8 एस. सी. आर. 1129 पैरा 37

(2009) 15 एस. सी. आर. 836 पैरा 38

(2007) 7 एस. सी. आर. 1051 पैरा 38

(2009) 1 एस. सी. आर. 672 पैरा 38

(2005) 2 एस. सी. 659 पैरा 39

(2012) 11 एस. सी. आर. 174 पैरा 45

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार:-आपराधिक अपील संख्या 775/2017

आपराधिक अपील संख्या 568/2010 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के दिनांकित 30.06.2016 और 07.07.2016 के निर्णय और आदेश से।

संचार आनंद, अपूर्व सिंघल, अनंत के. वात्स्या, नरसिंह एन. राय, डॉ. सुशील बलवाड़ा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

डी. के. ठाकुर, एएजी, वरिंदर कुमार शर्मा, प्रतिवादी के वकील।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा द्वारा दिया गया था।

1. वर्तमान अपील, विशेष अनुमति द्वारा, एक युवा लड़की की दुखद कहानी को दर्शाती है, जो अपनी किशोरावस्था के बीच में, आरोपी-अपीलार्थी के प्यार में पड़ जाती है और उच्चतम स्तर के युवा निर्धारण से प्रेरित होती है, निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास में उसके साथ भाग जाती है, और जब आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (एल. पी. सी.) की धारा 363,366 और 376 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया जाता है, तो वह उसके पीछे एक विशालकाय व्यक्ति की तरह खड़ी होती है जो समर्थन करने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है जिसके परिणामस्वरूप उसे बरी कर दिया जाता है। सभी

संभावनाओं में, उसने महसूस किया होगा कि आरोपी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह भी समान रूप से दोषी थी। जो भी हो, अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार, उसे बरी करने का लाभ दिया गया था।

2. दुखद कहानी एक नई और अलग शुरुआत में आती है। अभियुक्त को लगता है कि अभियोजक के कारण उस पर मुकदमा चलाया गया है और वह लड़की को धमकी देने के विचार से ग्रस्त हो जाता है और यह जारी रहता है और अंततः छेड़छाड़ एक नियमित बात बन जाती है। यहाँ, जैसे ही अभियोजन पक्ष का बयान अप्रमाणित होता है, आरोपी द्वारा एक ऐसी स्थिति पैदा की जाती है जो असहनीय हो जाती है, जहाँ युवा लड़की आश्वस्त महसूस करती है और महसूस करती है कि वह अब शांति से नहीं रह सकती है। भावना अंतर्निहित हो जाती है और असहाय स्थिति उसे यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि जीवन जीने लायक नहीं है। नतीजतन, वह अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालती है और खुद को आग लगा लेती है लेकिन मृत्यु तुरंत नहीं आती है और उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के दौरान, उसकी मृत्युकालिक घोषणा दर्ज की जाती है, लेकिन वह अंततः अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देती है और "प्राण" शरीर को छोड़ देता है और वह एक "शरीर" बन जाती है-एक मृत।

3. जिस सवाल का जवाब दिया जाना आवश्यक है वह यह है कि क्या आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। अभियोजन पक्ष का मामला जैसा कि अनुमान लगाया गया है कि मृतक मुखबिर, पीडब्लू-1, सुख देव की बेटी थी और आईपीसी की धारा 363,366 और 376 के तहत मामले में बरी होने के बाद, आरोपी-अपीलकर्ता लड़की को धमकी देता था कि वह उसका अपहरण कर लेगा, और लगातार उसे छेड़ रहा था। अभियोजन पक्ष का मामला है कि 18.07.2008 को रात 9 बजे अपीलार्थी मुखबिर के घर आया और उसे धमकी दी कि वह उसे जबरन ले

जाएगा। जैसे-जैसे 19.07.2008 पर सुबह लगभग 10 बजे पर कहानी आगे बढ़ती है, जब मुखबिर अपनी पत्नी के साथ खेत में बाहर काम कर रहा था, तो मृतक ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली, जिसे पिता ने बुझा दिया और तुरंत ग्राम पंचायत के प्रधान को सूचित किया गया। घायल लड़की को दौलतपुर के निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उसे आगे के चिकित्सा उपचार के लिए चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया लेकिन मुखबिर उसे पैसों की कमी के कारण चंडीगढ़ नहीं ले जा सका और शाम को गांव के प्रधान ने मुखबिर के घर का दौरा किया और मृतक ने प्रधान को एक लिखित दस्तावेज दिया जिसमें कहा गया था कि आरोपी-अपीलकर्ता उसकी स्थिति के लिए जिम्मेदार था, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और मुखबिर का बयान दर्ज किया गया और पीड़ितकी चिकित्सकीय जांच की गई। 24.07.2008 को, लड़की की मृत्युकालिक घोषणा हेड कांस्टेबल द्वारा चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज की गई और पीड़ित की मृत्यु के बाद पोस्टमॉर्टम किया गया और एक प्राथमिकी दर्ज की गई। आपराधिक कानून के लागू होने के बाद, जांच एजेंसी ने जांच पूरी करने के बाद सक्षम अदालत के समक्ष आरोप पत्र रखा, जिसने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

4. अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और गलत निहितार्थ का अनुरोध किया। अभियोग स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों से पूछताछ की। बचाव पक्ष ने किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं करने का फैसला किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दलीलें सुनने के बाद निम्नलिखित प्रश्न पूछाः क्या अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेहों के दायरे से परे आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोपी के दायित्व को सफलतापूर्वक साबित किया है? और नकारात्मक में प्रश्न का उत्तर दिया और परिणामस्वरूप 16 जुलाई, 2010 के निर्णय और आदेश के माध्यम से अभियुक्त-अपीलार्थी को बरी कर दिया।

5. उपरोक्त निर्णय से व्यथित होने के कारण, राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया और आरोपी-अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया और उसे सात साल के कठोर कारावास और एक 10, 000/- जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माने का भुगतान न करने पर एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से गुजरना होगा।

6. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री संचार आनंद और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री डी. के. ठाकुर को सुना है।

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री आनंद द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय बिल्कुल त्रुटिहीन है क्योंकि उन्होंने साक्ष्य का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है और सही परिप्रेक्ष्य में उनकी सराहना की है। यह उनका आगे का निवेदन है कि निचली अदालत ने चिकित्सा साक्ष्य और पीड़ित को लगी चोटों की जांच करते हुए मृत्यु पूर्व घोषणा एक्स.पीडब्लू-10/ए. को खारिज कर दिया है। यह आगे कहा गया है कि जब निचली अदालत द्वारा मृत्यु पूर्व घोषणा और अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही पर भरोसा नहीं करने के लिए ठोस कारण बताए गए हैं, तो उच्च न्यायालय को, ऐसी तथ्य स्थिति में, बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करने की अच्छी तरह से सलाह दी जानी चाहिए थी। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि जब निचली अदालत द्वारा साक्ष्य की सराहना विकृत नहीं है और उसके द्वारा व्यक्त किया गया विचार प्रशंसनीय है, तो उच्च न्यायालय को बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

8. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री डी. के. ठाकुर, विवादित फैसले के समर्थन में तर्क देंगे कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का

पुनर्मूल्यांकन किया है और इस तरह के पुनर्मूल्यांकन पर पीड़ित की चिकित्सा स्थिति से संबंधित निष्कर्ष पूरी तरह से गलत पाया है और तदनुसार राय दी है कि विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया बरी होना असमर्थनीय है और इसलिए, इस न्यायालय को उसी के अनुमोदन की मुहर देनी चाहिए।

9. सबसे पहले हम उस क्षेत्राधिकार की प्रकृति से निपटेंगे जिसका प्रयोग उच्च न्यायालय तब करता है जब वह अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषसिद्धि के दोषमुक्ति के निर्णय को उलट देता है। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियुक्त द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को स्थापित करने में सक्षम रहा है और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को उलटना बिल्कुल त्रुटिहीन है। जदुनाथ सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी हैः -

> "22. इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय को बड़े पैमाने पर सभी साक्ष्यों की समीक्षा करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की पूरी शक्ति है कि उस साक्ष्य पर बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया जाना चाहिए। बरी किए जाने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की यह शक्ति शिव स्वरूप बनाम राजा सम्राट[2] और नूर मोहम्मद बनाम सम्राट[3] में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा तैयार की गई थी। इन दोनों निर्णयों को इस न्यायालय के निर्णयों में लगातार आपराधिक अपीलों की सुनवाई में एक अपीलीय अदालत की शक्ति के सही दायरे को

निर्धारित करने के रूप में संदर्भित किया गया है (सूरजपाल सिंह बनाम राज्य और संवत सिंह बनाम राजस्थान राज्य देखें)।

10. शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अपील न्यायालय की उस पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने की पूर्ण शक्ति में कोई बाधा नहीं है, जिस पर दोषमुक्त करने का आदेश स्थापित किया गया है और वास्तव में, इसकी जांच करना उसका कर्तव्य है, हालांकि, इस भारी विचार से सूचित किया गया है कि अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने के लिए जिम्मेदार खंडन योग्य निर्दोषता, न्यायशास्त्र की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सम्मान, उच्च न्यायालय को बहुत ही विश्वसनीय कारणों और व्यापक विचार के बिना निष्कर्ष को परेशान नहीं करने के लिए विवश करता है।

11. कर्नाटक राज्य बनाम के. गोपालकृष्णन के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां निचली अदालत के निष्कर्ष पूरी तरह से अनुचित या विकृत हैं और रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं या गंभीर अवैधता से पीड़ित हैं और इसमें अज्ञानता और रिकॉर्ड का गलत अध्ययन शामिल है, तो अपीलीय अदालत इस तरह के बरी करने के आदेश को रद्द करने में उचित होगी।

12. गिरजा प्रसाद (मृत) के कानूनी प्रतिनिधि बनाम एम. पी. राज्य मामले में, यह देखा गया है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय को अपने समक्ष साक्ष्य की पुनः सराहना, समीक्षा और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है। न्यायालय ने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि अभियुक्त के पक्ष में अप्रमाणिकता की धारणा है और यह धारणा निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के आदेश से प्रबलित होती है, लेकिन यह मामले का अंत नहीं है, क्योंकि यह अपीलीय न्यायालय पर है कि वह कानून के प्रासंगिक सिद्धांतों को ध्यान में रखे, साक्ष्य

की समग्र रूप से पुनः सराहना करे और पुनः मूल्यांकन करे और आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचे।

13. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजय कुमार मामले में राजस्थान राज्य बनाम सोहन लाल में बताए गए सिद्धांतों को दोहराया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि सोहन लाल (ऊपर) मामले में इस प्रकार कहा गया हैः-

> "3 .... इस न्यायालय ने बार-बार यह निर्धारित किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय, बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय भी, पूरे साक्ष्य की जांच करने और आवश्यकता पड़ने पर पुनः मूल्यांकन करने का हकदार था, और साथ ही बाध्य भी था, हालांकि केवल हस्तक्षेप करने का विकल्प चुनते समय न्यायालय को रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर अपराध का पूर्ण आश्वासन मिलना चाहिए, न कि केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय केवल एक और संभावित या अलग दृष्टिकोण ले सकता है। उपरोक्त के अलावा, जहां अपील पर विचार करने की सीमा और गहराई का संबंध है, किसी अपील पर विचार करने में कोई अंतर या दृष्टिकोण में मतभेद की परिकल्पना नहीं की गई है क्योंकि केवल एक दोषसिद्धि के खिलाफ था या दूसरा दोषमुक्ति के खिलाफ था। चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में, इस न्यायालय ने बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में सामान्य सिद्धांतों को समाप्त कर दिया। उक्त सिद्धांतों को नीचे सूचीबद्ध किया गया हैः -

14. चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य [11] में, इस न्यायालय ने बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान अपीलीय अदालत की शक्तियों के संबंध में सामान्य सिद्धांतों को हटा दिया। उक्त सिद्धांत नीचे दिए गए हैं: -

(1) एक अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और एक अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य पर कोई शर्त नहीं लगाता है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे 'पर्याप्त और सम्मोहक कारण', 'अच्छे और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत परिस्थितियाँ', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियाँ', आदि का उद्देश्य बरी होने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय अदालत की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह के वाक्यांश 'भाषा के विकास' की प्रकृति में अधिक हैं।

(4) एक अपीलीय अदालत को, हालांकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत निर्दोषता का अनुमान उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष

माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता। दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और मजबूत, पुनः पुष्ट और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष में बाधा नहीं डालनी चाहिए। जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा। दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और मजबूत, पुनः पुष्ट और मजबूत किया जाता है।

(6) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निष्कर्ष में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

15. शिवाजी साहबराव बोबडे (ऊपर) में, समकालीन संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहाः - "1. सामाजिक रक्षा की कीमत पर संदेह के लाभ के नियम के प्रति अतिरंजित समर्पण के खतरे और इस सुखदायक भावना के लिए कि पीड़ित और समुदाय के लिए न्याय की परवाह किए बिना सभी दोषमुक्त हमेशा अच्छे होते हैं, बढ़ते अपराध और पलायन के समकालीन संदर्भ में विशेष जोर देने की मांग करते हैं। न्यायिक साधन में सार्वजनिक जवाबदेही होती है। उचित संदेह से परे सबूत के पोषित सिद्धांत या सुनहरे धागे जो हमारे कानून के जाल में चलते हैं, उन्हें हर आशंका, हिचकिचाहट और संदेह की डिग्री को गले लगाने के लिए विकृत रूप से नहीं फैलाया

जाना चाहिए। एक हजार दोषी पुरुष जा सकते हैं लेकिन एक निर्दोष शहीद को नुकसान नहीं होगा, इस रवैये में दिखाई देने वाला अत्यधिक आग्रह एक झूठी दुविधा है। केवल उचित संदेह अभियुक्त के हैं। अन्यथा न्याय की कोई भी व्यावहारिक प्रणाली तब टूट जाएगी और समुदाय के साथ विश्वसनीयता खो देगी। जैसा कि एक विद्वान लेखक ने स्पष्ट रूप से देखा है कि एक दोषी व्यक्ति को हल्के-फुल्के दिल से बरी करने की बुराई इस सरल तथ्य से बहुत आगे जाती है कि केवल एक दोषी व्यक्ति को दंडित नहीं किया गया है. यदि बिना शर्त बरी किए जाने की घटना सामान्य हो जाती है, तो वे कानून की सनकी अवहेलना की ओर ले जाते हैं, और इससे अभियुक्त "व्यक्तियों" के खिलाफ कठोर कानूनी अनुमान लगाने और दोषी पाए जाने वालों को अधिक कठोर सजा देने की सार्वजनिक मांग होती है। इस प्रकार, दोषियों को बार-बार बरी करने से एक क्रूर दंडात्मक कानून बन सकता है, जो अंततः निर्दोष लोगों के न्यायिक संरक्षण को नष्ट कर सकता है। इन सभी कारणों से, विस्काउंट साइमन के साथ यह कहना सही है कि "निर्दोष के दोषसिद्धि से कम से कम दोषी के बरी होने से न्याय का गर्भपात हो सकता है।" संक्षेप में, अनुमानित निर्दोषता के लिए हमारे न्यायशास्त्रीय उत्साह को आपराधिक न्याय को शक्तिशाली और यथार्थवादी बनाने की व्यावहारिक आवश्यकता से नियंत्रित किया जाना चाहिए।

16. उपरोक्त प्राधिकारियों के निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम विद्वत विचारण न्यायाधीश के दृष्टिकोण की जांच करेंगे और उच्च न्यायालय के विचार-विमर्श की शुद्धता की जांच करेंगे और विचारण न्यायालय के फैसले को अंतिम रूप से उलटने का निर्णय लेंगे।

17. ट्रायल कोर्ट के फैसले की सावधानीपूर्वक जांच और बारीकी से अध्ययन करने पर, यह माना जा सकता है कि विद्वत ट्रायल जज ने तथ्यों को गिनने के बाद,

सबूतों का विश्लेषण किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष आरोपी की दोषसिद्धि को साबित करने में विफल रहा है। उन्होंने मृतक के पिता पीडब्लू-1, सुख देव के साक्ष्य पर मुख्य आधार पर अविश्वास किया है कि हालांकि आईपीसी की धाराओं के तहत अपराध के लिए स्थापित आपराधिक मामले में आरोपी को बरी करने के बाद, उन्होंने अपनी बेटी को छेड़ा, फिर भी उन्होंने केवल ग्राम पंचायत में मौखिक शिकायत की और उसके समक्ष लिखित शिकायत दर्ज नहीं की। इसके अलावा, विद्वत ट्रायल जज ने नोट किया है कि हालांकि पीडब्लू-। ने प्राथमिकी में कहा था कि आरोपी ने उसकी बेटी को जबरन ले जाने की धमकी दी थी, लेकिन उसने अपने बयान में ऐसा नहीं कहा था। मृत्यु पूर्व घोषणा यानी, Ex. पीडब्लू-10/ए, को इस आधार पर विश्वास नहीं दिया गया है कि पीड़ित बोलने की स्थिति में नहीं थी और उसे 80 प्रतिशत जलने की चोटें आई थीं और इसके अलावा क्योंकि उसके दोनों हाथ जल गए थे, इसलिए वह वह नहीं लिख सकती थी जो कथित रूप से उसके द्वारा उक्त दस्तावेज़ में लिखा गया था, इस आधार पर विद्वत परीक्षण न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त मृत्यु पूर्व घोषणा पर भरोसा करना सही नहीं होगा। पीडब्लू-10/ए मृतक द्वारा 24.07.2008 को लिखा गया था। उन्होंने उसी आधार पर भौतिक गवाहों की गवाही पर भी अविश्वास किया है।

18. जैसा कि साबित लायक़ है, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने भी Ex. पीडब्लू-10/ए को नहीं पाया है, जिसे जांच अधिकारी, पीडब्लू-13 द्वारा 24.07.2008 पर दर्ज किया गया था, उतना ही विश्वसनीय था जितना कि पीड़ित का इलाज चल रहा था और चिकित्सा अधिकारी पीडब्लू-10, डॉ. संजय, जिन्होंने बयान दिया था कि उन्होंने पीडब्लू-10/बी में अपना समर्थन जोड़ा था, लेकिन कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया कि पीड़ित अपना बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी। विद्वान परीक्षण न्यायाधीश ने कहा है कि उपरोक्त साक्ष्य को छोड़कर, आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर कोई और सबूत नहीं है. यह ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का

उल्लेख किया है जिसमें दर्ज किया गया है कि पीड़ित को जलने की चोटें आई थीं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरोपी के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए कोई विशिष्ट सबूत नहीं है।

19. उच्च न्यायालय ने, जैसा कि ध्यान देने योग्य है, इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि पीडब्लू-1 ने गवाही दी है कि आरोपी ने पहले आई. पी. सी. की धारा 363,366 और 376 के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना किया था और ग्यारह महीने तक जेल में रहा और इसलिए उसने पीड़ितको धमकी दी कि वह फिर से उसका अपहरण कर लेगा। इसके अलावा, मृतक के पिता पीडब्लू-1 सुख देव ने यह भी बयान दिया था कि आरोपी इशारे से उसकी बेटी को छेड़ता था और उसकी बेटी उसे और उसकी पत्नी को ये तथ्य बताती थी। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने ग्राम पंचायत, बाथरा के प्रधान को मौखिक शिकायत की थी, जिन्होंने अपनी ओर से आरोपी को फटकार लगाई थी और उन्हें अपने तरीके सुधारने के लिए कहा था। उच्च न्यायालय ने आगे इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पीडब्लू-1 ने उनकी बेटी को लगी चोटों और उसके कारण का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है।

20. पीडब्लू-2, जय सिंह, जैसा कि उनके साक्ष्य से पता चलता है, जो कि उच्च न्यायालय द्वारा भी ध्यान में रखा गया है, गाँव के प्रधान हैं। उसने आरोपी के आचरण के बारे में गवाही दी है और कैसे उसने उसे स्थिति को समझने के लिए कहा था। उसने पीड़ित को अस्पताल ले जाने और उसे दिए गए उपचार की प्रकृति के बारे में भी बयान दिया है। उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-3, डॉ. कुलभूषण सूद के साक्ष्य पर भी विचार किया है, जिन्होंने एमएलसी, एक्सपीडब्लू-3/बी जारी किया था, ने स्वीकार किया कि पीड़ित को 80 प्रतिशत जलने की चोटें आई थीं और राय दी कि यह रोगी की मानसिक क्षमता को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। उच्च न्यायालय ने मृतक की मां पी.

डब्ल्यू.-9, स्वर्ण देवी के साक्ष्य का भी विश्लेषण किया है, जिन्होंने पूरी घटना के बारे में गवाही दी है। पीडब्लू-10, डॉ. संजय, जिन पर उच्च न्यायालय ने भारी निर्भरता रखी है, को आर. पी. जी. एम. सी., टांडा में शल्य चिकित्सा विभाग में वरिष्ठ रेज़ीड़ेंट के रूप में तैनात किया गया था। पुलिस ने मौखिक रूप से उनसे उनके साथ जाने का अनुरोध किया था क्योंकि पीड़ित का बयान दर्ज किया जाना था और 24.07.2008 और वह उस वार्ड में गया जहाँ पीड़ित था और घायल का बयान पुलिस, एक्सपीडब्लू-10/ए, द्वारा उनकी उपस्थिति में दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का भी जिक्र की है कि जिरह में इलाज कर रहे डॉक्टर ने स्वीकार किया था कि उसने कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था कि पीड़ित बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ था। यह उल्लेख करना उचित है कि उक्त गवाह ने इस सुझाव का खंडन किया है कि पीड़ित बयान देने के योग्य नहीं था और पूर्व। एक्सपीडब्लू-10/ए उनका बयान नहीं था।

21. साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया है कि निचली अदालत ने आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया है कि मृतक एक्सपीडब्लू-10/ ए लिखने के योग्य नहीं था और पीडब्लू-10, डॉ. संजय ने 24.07.2008 को बयान देने के लिए यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था कि मृतक स्वस्थ मानसिक स्थिति में था। उच्च न्यायालय ने कहा है कि उसने Ex. पीडब्लू-10/ए का विश्लेषण किया था। जहाँ से यह परिलक्षित होता था कि पीड़ित ने लिखा था कि उसकी मौत के लिए आरोपी जिम्मेदार होगा। उच्च न्यायालय का विश्लेषण इस प्रकार हैः-"यह लिखावट से स्पष्ट है कि शालू को बहुत दर्द और पीड़ा हुई थी जब वह लिख रही थी कि उसकी मौत के लिए आरोपी जिम्मेदार होगा। यह 19.7.2008 को लिखा गया था। यह प्रधान द्वारा Ex.पीडब्लू-2/ए में भी लिखा गया है कि शालू को जलने की चोटें आई थीं और उसने उसे बताया कि आरोपी उसे छेड़ता था। इस प्रकार उसने यह चरम कदम उठाया है। पीडब्लू-1 सुख देव और उनकी पत्नी (पीडब्लू-9) स्वर्ण देवी के बयान में कहा गया है कि

आपराधिक मामले में बरी होने के बाद भी आरोपी उनकी बेटी को छेड़ता था। उन्होंने इस तथ्य की जानकारी ग्राम पंचायत के प्रधान पीडब्लू-2 जय सिंह को दी थी। जय सिंह (पीडब्लू-2) ने भी स्वीकार किया है कि उसके पास शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसने आरोपी को अपना रास्ता सुधारने के लिए कहा है। और फिर सेः-"पीडब्लू-13 एस. आई. सुरजीत सिंह ने मृतक का बयान 24.7.2008 को Ex.पीडब्लू-10/ए के माध्यम से दर्ज किया है। पीडब्लू-10 डॉ. संजय ने बयान दिया है कि पुलिस ने शालू का बयान उसकी उपस्थिति में दर्ज किया था। उन्होंने समर्थन Ex.पीडब्लू-10/बी को प्रमाणित किया। पुलिस ने वही संस्करण एक्सपीडब्लू-10/ए में लिखा है। जिसे शालू ने स्टेटमेंट Ex.पीडब्लू-10/ए द्वारा बताया गया था। Ex.पीडब्लू-10/ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत एक मृत्यु पूर्व घोषणा का गठन करेगा। केवल यह कि डॉक्टर ने यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है कि शालू बयान देने के लिए उपयुक्त थी, किसी भी तरह से मृतक द्वारा 24.07.2008 पर की गई मृत्यु पूर्व घोषणा को प्रभावित नहीं करेगा, वह भी पीडब्लू-10 डॉ. संजय की उपस्थिति में। अभियोजन पक्ष द्वारा यह विधिवत साबित किया जाता है कि मृतक द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए अकेले आरोपी जिम्मेदार था। उसे मृत्युपूर्व 80-85% अगंभीर जलने की चोटें आई। हो सकता है कि उसे 80-85% जलन हुई हो, लेकिन फिर भी उसके पास एक्सपीडब्लू-2/ए लिखने की पर्याप्त ताकत थी।" उच्च न्यायालय ने गुलजारी लाल बनाम हरियाणा राज्य के मामले में निर्णय पर भरोसा किया है और यह माना है कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा घोषणाकर्ता की योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना एक वैध मृत्यु पूर्व घोषणा की जा सकती है।

22. यह स्पष्ट है कि निचली अदालत ने मृतक के माता-पिता और अन्य गवाहों के बयान की अवहेलना करके और मृत्यु पूर्व घोषणा को अमान्य मानते हुए आरोपी को बरी कर दिया है और इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने मृतक के माता-पिता की

गवाही और ग्राम प्रधान के साक्ष्य पर भरोसा किया है और मृत्यु पूर्व घोषणा पर भी विश्वास दिखाया है।

23. जैसा कि देखा जाता है, विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा मृत्यु पूर्व घोषणा पर गैर-निर्भरता इस कारण पर आधारित है कि मृतक बोलने की स्थिति में नहीं था और उसकी योग्यता के संबंध में कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था। इसके अलावा, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने मृत्यु घोषणा को इस आधार पर अस्वीकार्य और अविश्वसनीय माना है कि मृतक को 80 प्रतिशत जलने की चोटें आई थीं। उच्च न्यायालय ने उक्त दृष्टिकोण को बिल्कुल गलत पाया है।

24. इस मामले का केंद्र यह है कि क्या मृत्यु पूर्व घोषणा पीडब्लू-10/ए को विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए। मृत्यु घोषणा की वैधता की विवेचना करने के लिए, हमने मूल अभिलेख की मांग की है और उसी पर विचार किया है। उसी की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, हम पाते हैं कि हेड कांस्टेबल ने वही लिखा था जो मृतक ने कहा था और उसके बाद मृतक ने लिखा था कि उसकी मौत के लिए केवल आरोपी ही जिम्मेदार था। मृत्यु पूर्व घोषणा, जैसा कि हेड कांस्टेबल द्वारा दर्ज किया गया है, आरोपी द्वारा पीड़ित को लगातार चिढ़ाने के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है। पीडब्लू-10, डॉ. संजय, अपनी गवाही में दृढ़ रहे हैं कि पीड़ित बोलने के लिए उपयुक्त स्थिति में था। लगातार जिरह के बावजूद वो अपने से मार्ग डिगे नहीं है। ट्रायल कोर्ट, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ने पीडब्लू 10 की गवाही की इस आधार पर अवहेलना की है कि फिटनेस का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। इस संदर्भ में, लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य 14 में संविधान पीठ के फैसले का संदर्भ बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है। उक्त मामले में, वृहद पीठ ने मृत्यु पूर्व घोषणा से संबंधित कानून का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त रूप से कहा है:-

"3. मृत्यु पूर्व घोषणा मौखिक या लिखित हो सकती है और संचार का कोई भी पर्याप्त तरीका चाहे शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या अन्यथा पर्याप्त होगा बशर्ते संकेत सकारात्मक और निश्चित हो। हालांकि, ज्यादातर मामलों में, इस तरह के बयान मौत से पहले मौखिक रूप से दिए जाते हैं और मजिस्ट्रेट या डॉक्टर या पुलिस अधिकारी जैसे किसी व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं। जब इसे दर्ज किया जाता है, तो किसी शपथ की आवश्यकता नहीं होती है और न ही मजिस्ट्रेट की उपस्थिति बिल्कुल आवश्यक होती है, हालांकि प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट को बुलाना सामान्य है, यदि किसी व्यक्ति का बयान दर्ज करने के लिए उपलब्ध हो जो मरने वाला है। कानून की कोई आवश्यकता नहीं है कि मजिस्ट्रेट को मृत्यु घोषणा अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए और जब ऐसा बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है तो इस तरह की रिकॉर्डिंग के लिए कोई निर्दिष्ट वैधानिक रूप नहीं होता है। नतीजतन, इस तरह के बयान के साथ क्या प्रमाणिक मूल्य या वजन जोड़ा जाना चाहिए, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अनिवार्य रूप से जो आवश्यक है वह यह है कि जो व्यक्ति मृत्यु की घोषणा दर्ज करता है, उसे संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक मन की स्वस्थ स्थिति में था। जहां मजिस्ट्रेट की गवाही से यह साबित हो जाता है कि घोषणाकर्ता डॉक्टर द्वारा जांच किए बिना भी बयान देने के लिए उपयुक्त था, घोषणा पर कार्रवाई की जा सकती है बशर्ते कि अदालत अंततः इसे स्वैच्छिक और सच्चा मानती है। डॉक्टर द्वारा प्रमाणन

अनिवार्य रूप से सावधानी का एक नियम है और इसलिए घोषणा की स्वैच्छिक और सच्ची प्रकृति को अन्यथा स्थापित किया जा सकता है।

25. अतबीर बनाम एन. सी. टी. दिल्ली सरकार के मामले में, न्यायालय ने पहले के फैसलों पर ध्यान देने के बाद, मृत्यु पूर्व घोषणा की स्वीकार्यता के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए हैंः -

"22. उपरोक्त निर्णयों के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चलता है किः

(i) मृत्यु पूर्व घोषणा दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है यदि यह न्यायालय के पूर्ण विश्वास को प्रेरित करता है।

(ii) न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि बयान देते समय मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ था और यह शिक्षण, उकसाने या कल्पना का परिणाम नहीं था।

(iii) जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि घोषणा सत्य और स्वैच्छिक है, वह अपनी दोषसिद्धि को आधार बना सकता है, बिना किसी और पुष्टि के ।

(iv) यह कानून के एक पूर्ण नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु पूर्व घोषणा दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। पुष्टि की आवश्यकता केवल विवेक का एक नियम है।

(v) जहां मृत्यु की घोषणा संदिग्ध है, उस पर पुष्टि करने वाले साक्ष्य के बिना कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

(vi) मृत्यु पूर्व घोषणा जो दुर्बलता से ग्रस्त है जैसे कि मृतक बेहोश था और कभी भी कोई बयान नहीं दे सकता था, वह दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है।

(vii) केवल इसलिए कि मृत्यु पूर्व घोषणा में घटना के बारे में सभी विवरण नहीं होते हैं, इसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

(viii) भले ही यह एक संक्षिप्त बयान हो, इसे त्याग नहीं किया जाना चाहिए।

(ix) जब प्रत्यक्षदर्शी पुष्टि करता है कि मृतक मृत्यु की घोषणा करने के लिए योग्य और सचेत स्थिति में नहीं था, तो चिकित्सा राय प्रबल नहीं हो सकती है।

(x) यदि सावधानीपूर्वक जांच के बाद, अदालत का समाधान हो जाता है कि मृतक को गलत बयान देने के लिए प्रेरित करने के लिए यह समय और किसी भी प्रयास से मुक्त है और यदि यह सुसंगत और सुसंगत है, तो इसे दोषसिद्धि का आधार बनाने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं होगी, भले ही कोई पुष्टि न हो।

26. हाल ही में, गुलजारी लाल (ऊपर) मामले में, अदालत ने लक्ष्मण (ऊपर) में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर मृतक द्वारा दिए गए और हेड कांस्टेबल द्वारा दर्ज किए गए बयान पर भरोसा करते हुए दोषसिद्धि की पुष्टि की। उक्त मामले में विश्लेषण इस प्रकार हैः

"23. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की स्थिति के संदर्भ में, हमें मृतक की मृत्यु पूर्व घोषणा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का

कोई कारण नहीं मिलता है क्योंकि हेड कांस्टेबल मनफूल सिंह (पीडब्लू 7) द्वारा अपना बयान दर्ज करते समय, वह घटना के संबंध में अपना बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ पाया गया था। इसके अलावा, हेड कांस्टेबल मनफूल सिंह (पीडब्लू 7) के साक्ष्य को विश्वसनीय दिखाया गया था और नीचे दी गई अदालतों द्वारा स्वीकार किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और वही क्रम में है।

24. उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि न केवल महासिंह (मृतक) द्वारा दिए गए बयानों पर आधारित थी, बल्कि चश्मदीद गवाह दारीया सिंह (पीडब्लू 1) और स्वतंत्र गवाह राजिंदर सिंह (पीडब्लू 11) के बयान पर भी आधारित थी।

25. उपरोक्त अधिकारियों के आदेश पर परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि मृत्यु पूर्व घोषणा की अवहेलना करने का कोई कारण नहीं है। हेड कांस्टेबल ने इसे मृतक द्वारा सुनाई गई कहानी के रूप में दर्ज किया है और मृतक ने आरोपी के बारे में कुछ शब्द भी लिखे हैं। यही बात डॉक्टर, पीडब्लू-10 की उपस्थिति में दर्ज की गई है, जिन्होंने उनके हस्ताक्षर किए थे। फिटनेस का प्रमाण पत्र कानून की आवश्यकता नहीं है। निचली अदालत मसूड़े की चोटों से विचलित हो गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि एक पूर्ण नियम नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसे 80 प्रतिशत चोटें लगी हैं, वह मृत्यु पूर्व घोषणा नहीं कर सकता है।"

27. विजय पाल बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) के मामले में, अदालत ने मृतक द्वारा की गई मृत्यु पूर्व घोषणा के संबंध में प्रस्तुतिकरण को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था किः-

> "22 इस प्रकार, कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि मृत्यु पूर्व घोषणा पूरी तरह से विश्वसनीय है और रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया जाता है कि मृतक ऐसी स्थिति में था, तो वह किसी गवाह के सामने मृत्यु की घोषणा नहीं कर सकता था, तो इसे त्यागने का कोई औचित्य नहीं है। तत्काल मामले में, पीडब्लू 1 तुरंत मृतक के घर पहुंची और उसने उसे बताया कि उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल डाला था। अपीलार्थी द्वारा की गई याचिका कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है क्योंकि उसका पैसा ससुराल वालों के पास जमा किया गया था और वे वापस लौटने के लिए इच्छुक नहीं थे; वास्तव में सच्चाई की सांस नहीं लेता है, क्योंकि इस आशय का कोई सुझाव भी नहीं है।

23. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जब मृतक को 100% जलने की चोटें लगी हैं, तो उसने अपने भाई को कोई बयान दिया है। इस संबंध में, हम लाभप्रद रूप से माफाभाई नगरभाई रावल बनाम गुजरात राज्य के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें यह माना गया है कि 99 प्रतिशत मसूड़ों की चोटों से पीड़ित व्यक्ति को मृत्यु पूर्व घोषणा करने के उद्देश्य के लिए पर्याप्त सक्षम माना जा सकता है। उक्त मामले में न्यायालय ने राय दी कि जब तक कुछ अंतर्निहित और स्पष्ट दोष मौजूद नहीं है, तब तक निचली

अदालत को डॉक्टर की राय के स्थान पर अपनी राय नहीं रखनी चाहिए थी। मामले के तथ्यों के आलोक में, मृत्यु पूर्व घोषणा को निर्भरता के योग्य पाया गया।

28. उपरोक्त के अलावा, उसकी मृत्यु पूर्व घोषणा को अन्य गवाहों से समर्थन मिला है। पुष्टि करने वाले साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर सही ढंग से भरोसा किया है और निचली अदालत के निष्कर्ष को उलट दिया है।

29. जहाँ तक पीडब्लू-1 और पीडब्लू-9 के साक्ष्य की विश्वसनीयता का सवाल है, पीड़ित के माता-पिता का कहना है कि उनके बयान को विश्वसनीय नहीं मानने के कारण इस तथ्य पर आधारित हैं कि उन्होंने ग्राम पंचायत को लिखित रूप में घटना की सूचना नहीं दी थी। साक्ष्य को पूरी तरह से देखने पर, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा किए गए विश्लेषण को उचित रूप से हटा दिया है। विभिन्न परिस्थितियों के संबंध में साक्ष्य की सराहना की जानी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरोपी को पहले के अपराध में बरी कर दिया गया है और वह पीड़ित के लिए लगातार उपद्रव बन गया है। ऐसे में गरीब माता-पिता के पास ग्राम पंचायत में शिकायत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह मानना कि उनका साक्ष्य निंदनीय है क्योंकि शिकायत लिखित रूप में नहीं दी गई थी, विकृत दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। साक्ष्य को पूरी तरह से देखने पर, हम पाते हैं कि माता-पिता की गवाही पूरी तरह से निर्विवाद है और विश्वास के योग्य है।

30. अगला पहलू जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या आई. पी. सी. की धारा 307 आईपीसी की धारा 306 लगती है। अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का निवेदन यह है कि यह मानते हुए भी कि आरोप साबित हो गया है,

यह आई. पी. सी. की धारा 306 के दायरे और दायरे में नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई उकसावा नहीं है।

31. आई. पी. सी. की धारा 306 निम्नानुसार हैः- "धारा 306, किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने पर, जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उसे दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

32. आई. पी. सी. की धारा 307 में 'उकसाना' शब्द की व्याख्या नहीं की गई है। इस संदर्भ में, आई. पी. सी. की धारा 107 के तहत प्रदान की गई उकसाने की परिभाषा प्रासंगिक है। आई. पी. सी. की धारा 306 उन लोगों को दंडित करने का प्रयास करती है जो दूसरों को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं। व्यक्ति ने दूसरे को आत्महत्या के लिए उकसाया है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से एकत्र किया जाना चाहिए और आरोपी के निरंतर आचरण से पता लगाया जाना चाहिए, जिसमें उसका मानसिक तत्व शामिल है। ऐसी आवश्यकता को आई. पी. सी. की धारा 107 को पढ़ने से समझा जा सकता है।

आई. पी. सी. की धारा 107 इस प्रकार हैः-

> "धारा 107, किसी चीज़ को बढ़ावा देना-एक व्यक्ति किसी चीज़ का ए करने में मदद करता है, जो-- प्रथम - किसी भी व्यक्ति को वह काम करने के लिए उकसाता है; या दूसरा- उस कार्य को करने के लिए किसी भी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संलग्न होना, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होती है, और उस कार्य को करने के लिए; या तीसरा - किसी भी

कार्य या अवैध चूक से जानबूझकर उस कार्य को करने में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1-एक व्यक्ति जो जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करके, या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाकर, जिसे वह प्रकट करने के लिए बाध्य है, स्वेच्छा से किसी कार्य को करने का कारण बनता है या प्राप्त करता है, या करने का प्रयास करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, कहा जाता है कि वह उस कार्य को करने के लिए उकसाता है। चित्रण-ए, एक सार्वजनिक अधिकारी, जेड को पकड़ने के लिए न्यायालय के वारंट द्वारा अधिकृत है। बी, इस तथ्य को जानते हुए और यह भी कि सी जेड नहीं है, जानबूझकर ए को दर्शाता है कि सी जेड है, और इस तरह जानबूझकर ए को सी को पकड़ने के लिए प्रेरित करता है। "प्रोत्साहन", इस प्रकार, कार्य करने के लिए सक्रिय सुझाव या समर्थन की निश्चित मात्रा का अर्थ है।

33. आई. पी. सी. की धारा 107 में पाए जाने वाले "उकसाने" की अवधारणा का विश्लेषण करते हुए, चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा हैः-

"13. धारा के अनुसार, एक व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाया गया कहा जा सकता है, यदि वह, सबसे पहले, किसी व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए उकसाता है; या दूसरा, उस कार्य को करने के लिए किसी भी साजिश में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ शामिल होता है, यदि उस साजिश के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होती है, और उस कार्य को करने के लिए;

या तीसरा, जानबूझकर किसी भी कार्य या अवैध चूक द्वारा, उस कार्य को करने में सहायता करता है। धारा 107 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि कोई भी जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करना या भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाना, जिसे वह प्रकट करने के लिए बाध्य है, "उकसाने" के दायरे में भी आ सकता है। यह स्पष्ट है कि तीनों स्थितियों में, आई. पी. सी. की धारा 306 के तहत अपराध को घर लाने के लिए आत्महत्या के अपराध में संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों की प्रत्यक्ष भागीदारी आवश्यक है।

xxxxx

15. उक्त धारा के खंड प्रथम के अनुसार, उस व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाने वाला कहा जा सकता है, जो किसी भी व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए "उकसाता" है। आईपीसी में "उकसाना" शब्द परिभाषित नहीं है । उक्त शब्द के अर्थ पर इस न्यायालय द्वारा रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [19] में विचार किया गया था।" उक्त प्राधिकार में, विद्वान न्यायाधीशों ने रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में दिए गए फैसले का उल्लेख किया है ।

34. "उकसाना" शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए उकसाना, आगे बढ़ना, भड़काना, उकसाना या प्रोत्साहित करना। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तब उकसाता है जब वह उसे किसी भी माध्यम या भाषा से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कार्य के लिए सक्रिय रूप से सुझाव देता है या उत्तेजित करता है, चाहे वह स्पष्ट आग्रह या संकेत, आग्रह या प्रोत्साहन का रूप लेता हो। उकसावे (व्यक्त) शब्दों में हो सकता है या (निहित) आचरण से हो सकता है।

35. शब्द "आगे बढ़ने का आग्रह" का अर्थ है किसी को कुछ करने के लिए सलाह देना या मनाने के लिए कड़ी मेहनत करना, किसी व्यक्ति को विशेष दिशा में अधिक तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति को धक्का देना या मजबूर करना। इसलिए, दूसरे को उकसाने वाले व्यक्ति को दूसरे को उकसाने, उकसाने या प्रोत्साहित करने के इरादे से उसे "उकसाना" या "आगे बढ़ाना" होता है। उकसावे को साबित करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि आरोपी मृतक को तब तक शब्दों, तानों से उकसाता या परेशान करता रहा जब तक कि मृतक ने प्रतिक्रिया नहीं की। एक आकस्मिक टिप्पणी या नियमित या सामान्य बातचीत में कही गई किसी बात को "उकसाने" के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या गलत नहीं समझा जाना चाहिए।

36. रणधीर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य [20] मामले में आगे विश्लेषण करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार देखा है: -

> "12. उकसावे में किसी व्यक्ति को उकसाने या जानबूझकर उस व्यक्ति को कोई काम करने में मदद करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है। साजिश के मामलों में भी इसमें उस चीज़ को करने के लिए साजिश में शामिल होने की मानसिक प्रक्रिया शामिल होगी। किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध करने के लिए उकसाने से पहले अधिक सक्रिय भूमिका की आवश्यकता होती है, जिसे किसी कार्य को करने के लिए उकसाने या सहायता करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है।" [जोर दिया गया]

37. प्रवीण प्रधान बनाम उत्तरांचल राज्य और एक अन्य में, यह शासन किया गया है:- "18. वास्तव में, उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि किसी विशेष मामले की

परिस्थितियों से प्रेरणा लेनी होगी। यह पता लगाने के लिए कोई स्ट्रेटजैकेट सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि क्या किसी विशेष मामले में उकसाहट हुई है जिसने व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। किसी विशेष मामले में, उकसावे के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हो सकता है जिसका आत्महत्या से सीधा संबंध हो सकता है। इसलिए, ऐसे मामले में, परिस्थितियों से एक निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए और यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिन्होंने वास्तव में ऐसी स्थिति पैदा की थी कि एक व्यक्ति ने पूरी तरह से निराश महसूस किया और आत्महत्या कर ली।

38. अमलेंदु पाल उर्फ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में, न्यायालय ने रणधीर सिंह (उपरोक्त), किशोरी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और किशनगिरी मंगलगिरी गोस्वामी बनाम गुजरात राज्य मामले में अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए कहा हैः "12 इस प्रकार, इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि किसी अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 306 के तहत अपराध का दोषी ठहराने से पहले, न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की ईमानदारी से जांच करनी चाहिए और मूल्यांकन भी करना चाहिए। यह पता लगाने के लिए कि क्या पीड़ित के साथ की गई क्रूरता और उत्पीड़न ने पीड़ित के पास अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा था, उसके सामने सबूत पेश किए गए। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आत्महत्या के कथित उकसावे के मामलों में आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने के कृत्यों का प्रमाण होना चाहिए। केवल आरोपी की ओर से घटना के समय के निकट कोई सकारात्मक कार्रवाई किए बिना उत्पीड़न के आरोप पर, जिसके कारण व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया या मजबूर किया गया, आई. पी. सी. की धारा 306 के संदर्भ में दोषसिद्धि धारणीय नहीं है।

39. नेताई दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आई. पी. सी. की धारा 107 के तहत विशेष रूप से सुसाइड नोट के संदर्भ में उकसाने की अवधारणा पर विचार करते हुए कहाः-

> "6. सुसाइड नोट में, दो स्थानों पर अपीलार्थी के नाम का उल्लेख करने के अलावा, किसी भी कार्य या घटना का कोई संदर्भ नहीं है जिसमें अपीलार्थी पर कोई जानबूझकर कार्य या चूक करने का आरोप लगाया गया है या जानबूझकर मृतक प्रणब कुमार नाग को आत्महत्या करने में सहायता या उकसाया गया है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि अपीलार्थी ने किसी भी साजिश में कोई भूमिका या कोई भूमिका निभाई है, जिसने अंततः मृतक प्रणब कुमार नाग को उकसाया या आत्महत्या के लिए उकसाया।
>
> 7. सुसाइड नोट के अलावा, शिकायतकर्ता द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि अपीलार्थी किसी भी तरह से अपने भाई प्रणब कुमार नाग को परेशान कर रहा था। अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज मामला बिना किसी तथ्यात्मक आधार के है। कथित सुसाइड नोट की सामग्री किसी भी तरह से अपीलार्थी के खिलाफ अपराध नहीं बनाती है। अपीलार्थी के खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन का परिणाम केवल बिना किसी फलदायी परिणाम के अपीलार्थी के लिए सरासर उत्पीड़न होगा। हमारी राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में गंभीर त्रुटि की कि अपीलार्थी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट एक संज्ञेय अपराध के तत्वों का खुलासा करती है। इसमें अपीलार्थी के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं था। हम पाते हैं कि यह एक

उपयुक्त मामला है जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत असाधारण शक्ति का उपयोग किया जाना है। हम अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हैं और तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं।

40. इस मोड़ पर, हम चित्रेश कुमार चोपड़ा (ऊपर) के दो अनुच्छेदों को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं। वे हैंः -

"16. रमेश कुमार मामले (ऊपर) में तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, आर. सी. लाहोटी, जे. (जैसा कि उनके प्रभुत्व को तब कहा गया था) कि उकसाना "एक कार्य" करने के लिए उकसाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, उकसाना, उकसाना या प्रोत्साहित करना है। "उकसाने" की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए या जो "उकसाने" का गठन करता है, वह आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम का सूचक होना चाहिए। फिर भी परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। जहाँ अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूक या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की थीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, उस स्थिति में, एक "उकसावे" का अनुमान लगाना पड़ सकता है। वास्तव में परिणाम की इच्छा किए बिना क्रोध या भावना के अनुरूप बोले गए शब्द को उकसाना नहीं कहा जा सकता है।

19. जैसा कि रमेश कुमार (उपरोक्त) में देखा गया है, जहां आरोपी अपने कृत्यों या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, एक "उकसावे" का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है, यह स्थापित करना होगा किः (i) अभियुक्त मृतक को शब्दों, कार्यों या जानबूझकर चूक या आचरण से परेशान या परेशान करता रहा जो कि एक जानबूझकर मौन भी हो सकता है जब तक कि मृतक अपने कार्यों, शब्दों या जानबूझकर चूक या आचरण से मृतक को आगे बढ़ने के लिए प्रतिक्रिया या धक्का या मजबूर नहीं करता है; और (ii) कि आरोपी का इरादा ऊपर उल्लिखित तरीके से कार्य करते हुए मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, आग्रह करना या प्रोत्साहित करना था। निस्संदेह, आपराधिक मनःस्थिति की उपस्थिति उत्तेजना का आवश्यक सहवर्ती है। इस न्यायालय ने फिर कहाः-

"20. आत्महत्या का कारण क्या है, इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है क्योंकि मनुष्यों में आत्महत्या के विचार और व्यवहार जटिल और बहुआयामी हैं। एक ही स्थिति में अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग प्रतिक्रिया करते हैं और व्यवहार करते हैं क्योंकि वे प्रत्येक घटना में व्यक्तिगत अर्थ जोड़ते हैं, इस प्रकार आत्महत्या के लिए व्यक्तिगत भेद्यता के लिए लेखांकन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आत्महत्या का स्वरूप उसके मानसिक दर्द, भय और आत्म-सम्मान के नुकसान के आंतरिक व्यक्तिपरक अनुभव पर निर्भर करता है। इनमें

से प्रत्येक कारक किसी व्यक्ति के अपने जीवन को समाप्त करने की भेद्यता में महत्वपूर्ण और उत्तेजक योगदानकर्ता हैं, जो या तो आत्म सुरक्षा का प्रयास हो सकता है या असहनीय स्वयं से पलायन हो सकता है।

41. उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया है। चाहे यह स्पष्ट रूप से कहा जाए कि आरोपी की ओर से घटना के समय के निकट किसी भी सकारात्मक कार्रवाई के बिना उत्पीड़न का आरोप, जिसके कारण एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, आई. पी. सी. की धारा 307 के संदर्भ में दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है। एक अनौपचारिक टिप्पणी जो सामान्य मामलों में उत्पीड़न का कारण बन सकती है, उकसावे के दायरे में नहीं आएगी। केवल फटकार या गुस्से में एक शब्द उकसाने का दर्जा नहीं अर्जित करेगा। सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जो पीड़ित के लिए जीवन को समाप्त करने की स्थिति पैदा करे।

42. तत्काल मामले में, आरोपी ने अपने कृत्यों और अपने निरंतर आचरण से ऐसी स्थिति पैदा की थी जिसके परिणामस्वरूप मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। अभियुक्त के सक्रिय कृत्यों ने मृतक को अपने जीवन का अंत करने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा, हमें अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं मिलती है जो न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर करे कि आत्महत्या करने वाली पीड़ित सामान्य कलह, कलह और घरेलू जीवन में अंतर के प्रति अतिसंवेदनशील थी जो उस समाज के लिए काफी सामान्य थी जिससे पीड़ित संबंधित थी। दूसरी ओर, आरोपी ने पीड़ित के आत्मसम्मान और आत्मसम्मान को धूमिल करने में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिससे पीड़ित लड़की ने आत्महत्या कर ली।

वास्तव में, उसके साथ हुई क्रूरता ने उसे अपनी जीवन-चिंगारी को बुझाने के लिए प्रेरित किया है।

43. जैसा कि स्पष्ट है, उच्च न्यायालय ने केवल मृत्यु घोषणा के आधार पर बरी होने के फैसले को उलट नहीं दिया है। इसने माता-पिता और अन्य गवाहों के साक्ष्य पर भी भरोसा किया है। इसने ग्राम पंचायत के प्रधान के संस्करण को भी विश्वसनीय माना है। इन सभी गवाहों ने गवाही दी है कि आरोपी बरी होने के बाद लड़की को धमकी देने और चिढ़ाने में लगा हुआ था। उसने उसे शांति से रहने नहीं दिया।

44. उसका उत्पीड़न असहनीय और असह्य हो गया था। पिता ने अपदस्थ कर दिया था कि लड़की ने उन्हें कई मौकों पर बताया था और उन्होंने प्रधान से शिकायत की थी। ये सभी अभियुक्त द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका के बराबर हैं। यह ऐसी स्थिति नहीं है जब किसी व्यक्ति को ऋण चुकाने के लिए कहा जाता है तो उसका अपमान किया जाता है। यह ऐसी स्थिति नहीं है जहां किसी को एक ही कार्य पर अपमानित किया जाता है। यह पूरी तरह से एक अलग स्थिति है। गाँव में रहने वाली युवा लड़की को लगातार धमकाया और छेड़ा जाता था। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। इस बात के प्रमाण हैं कि माता-पिता समाज के गरीब वर्ग से हैं। जैसा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है, जब उनकी बेटी के मामले को चंडीगढ़ के अस्पताल में भेजा गया तो पिता उसका इलाज नहीं कर सकते थे। परिवार की निष्कपटता स्पष्ट है। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री से पता चलता है कि अभियुक्त का आचरण पूरी तरह से सक्रिय था।

45. ईव-टीज़िंग, जैसा कि पुलिस उप महानिरीक्षक और एक अन्य बनाम एस. समुथिरम में कहा गया है, एक हानिकारक, भयानक और घृणित प्रथा बन गई है। न्यायालय ने इसमें इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनालिस्टिक्स (जनवरी-

जून 1995 संस्करण) का उल्लेख किया है, जिसने छेड़छाड़ को पांच शीर्षों में वर्गीकृत किया है। (1) मौखिक छेड़छाड़; (2) शारीरिक छेड़छाड़; (3) मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न; (4) यौन उत्पीड़न; और (5) कुछ वस्तुओं के माध्यम से उत्पीड़न। वर्तमान मामला मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न के मामले को प्रमुखता से प्रस्तुत करता है। हम यह कहते हुए दुखी हैं कि एक सभ्य समाज में छेड़छाड़ शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए उत्पीड़न का कारण बन रही है जो केवल यह दर्शाती है कि महिलाओं के लिए आवश्यक सम्मान की भावना सामाजिक रूप से विकसित नहीं की गई है। एक पुरुष की तरह एक महिला की भी अपनी जगह होती है। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उतनी ही समानता प्राप्त है जितनी एक पुरुष को है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी के अनुसार गरिमा के साथ जीने के अधिकार का छेड़छाड़ के अप्रिय कृत्य में लिप्त होकर उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यह लैंगिक संवेदनशीलता और न्याय की मौलिक अवधारणा और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत एक महिला के अधिकारों को प्रभावित करता है। इसके अलावा यह एक महिला के अधिकार में एक लाइलाज सेंध लगाता है जो संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत उसके पास है। यह सोचने के लिए मजबूर किया जाता है कि इस देश में महिलाओं को शांति से रहने और गरिमा और स्वतंत्रता के साथ सशक्त जीवन जीने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है। यह ध्यान में रखना होगा कि उसे जीवन का अधिकार है और वह अपनी पसंद के अनुसार प्रेम करने का हकदार है। उसके पास एक व्यक्तिगत विकल्प है जिसे कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। सामाजिक रूप से इसका सम्मान किया जाना चाहिए। कोई भी महिला को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। उसे अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

46. सभ्य समाज में पुरुष वर्चस्ववाद के लिए कोई जगह नहीं है। भारत का संविधान महिलाओं को अनुकूल अधिकार प्रदान करता है और उक्त अधिकार संविधान के

अनुच्छेद 15 से बोधगम्य हैं। जब संविधान के तहत अधिकार प्रदान किया जाता है, तो यह समझना होगा कि कोई उपेक्षा नहीं है। एक आदमी को अपने अहंकार या उस मामले के लिए, मर्दानगी को एक आधार पर नहीं रखना चाहिए और सभ्यता की अवधारणा को नहीं छोड़ना चाहिए। अहंकार को कानून के आगे झुकना चाहिए। इस संदर्भ में समानता को संवैधानिक सिद्धांत का सारांश माना जाना चाहिए। तत्काल मामला अपीलार्थी की खेदजनक भ्रष्टता को दर्शाता है जिसके कारण एक युवा लड़की के लिए दिल दहला देने वाली स्थिति पैदा हो गई है जिसे अपने जीवन को समाप्त करने के लिए मजबूर किया गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को पूरी तरह से सही तरीके से उलट दिया है और सजा सुनाई है। इसने उपयुक्त रूप से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है और हम इससे सहमत हैं।

47. नतीजतन, अपील, किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण, खारिज हो जाती है।

अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।